

जल संग्रहण एवं प्रबन्धन: नई एवं पुरानी पद्धतियाँ

सारांश

जल का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि जन्म ले लेकर मृत्यु तक हमारा कोई भी सांस्कृतिक कर्म बिना जल के पूरा नहीं होता। और यह सिर्फ हमारे समाज तक सीमित बात नहीं है। दुनिया के हर समाज और धर्म में जल को सबसे पवित्र माना गया है। हमारी सभ्यता नदियों के किनारे ही फली-फूली। उपयोगितावाद की बंधी दौड़ में प्रकृति को हमने अपना गुलाम बना लिया और उसका अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया। नतीजा हमारे सामने है। पानी का सवाल जब भी हमारे सामने आता है तो बड़े बांध, बड़ी सरकारी योजनाएं सामने आ जाती हैं। इससे पानी के सवाल का फौरी हल भले निकल जाता है, लेकिन जल-संरक्षण की मूल समस्या वहीं की वहीं रहती है।

मुख्य शब्द : प्रकृति, जल, जल-संरक्षण।

प्रस्तावना

देश जल संकट के मुहाने पर है। औसतन प्रति व्यक्ति 1000 घनमीटर पानी ही उपलब्ध है। जबकि प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से पानी का नीचे आना जल संकट माना जाता है। अमेरिका में मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति 3000 घन मीटर पानी की उपलब्धता है। एक सच यह भी है कि देश में तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 65 प्रतिशत वर्षा का जल अब भी बेकार चला जाता है। इसका एकमात्र उपाय है जल संरक्षण, जल का चक्रीकरण।

हमारे ग्रामीण और शहरी जीवन में पुराने समय से चले आ रहे तालाब एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। तालाब खोदना प्रकृति के साथ मनुष्य की स्वाभाविक विकास यात्रा का क्रम था। आबादी के मध्य और दूर भी मनुष्य ने काफी संख्या में तालाब बनाये हैं। वर्षा का अतिरिक्त जल इन तालाबों में ही इकट्ठा होकर भूजल को समृद्ध करता रहा है लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की होड़ में धीरे-धीरे तालाबों की संख्या विलुप्त प्रायः होती जा रही है। जिला बिजनौर के धामपुर तहसील में एक समय तालाबों की संख्या काफी थी जोकि 90 के दशक तक आते-आते घटती गयी और आज लगभग पूर्ण रूप से खत्म होने के कगार पर है। आर.एस.एम. महाविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग के दो छात्रों ने अपने बी.एस.सी. तृतीय वर्ष के प्रोजेक्ट के लिए किए गये सर्वेक्षण में पाया कि धामपुर जोकि एक समय कई तालाबों से घिरा हुआ था, की संख्या घटकर 2 से 3 ही रह गयी है। इनकी घटती हुई संख्या का जहां उनमें रहने वाले जीव- जन्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वहीं मानव जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा है। छात्रों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि घटते हुए तालाबों की संख्या के कारण भूजल का स्तर घट/बढ़ रहा है क्योंकि तालाब प्राकृतिक हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य करते हैं। अतिवृष्टि के समय ये तालाब ही मानव बस्तियों को जल भराव से बचाते रहे हैं तो उफनाई नदियों का जल रोक कर बाढ़ की विभीषिका कम करने में भी सहायक हुए हैं। लगभग 20-25 प्रतिशत मनुष्य जो कि धामपुर एवं उसके आसपास के गांवों से हैं, का एक महत्वपूर्ण रोजगार का साधन मत्स्य पालन से लेकर सिंघाड़ा और इससे जुड़े अन्य उपयोग की खाद्य सामग्री धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही शहरीकरण की रफतार के कारण कई जीव-जन्तुओं का जोकि इन तालाबों में रहते आए हैं, को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचाया जा चुका है।

अध्ययन का उद्देश्य

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर इन तालाबों, चारागाहों, मैदानों जैसे इलाकों की रक्षा होने के स्थान पर बेहिसाब शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए इनका पाटना वैध बना दिया है। अब किसी भी योजना के तहत अधिग्रहित की गई जमीन पर तालाब, चरागाह या खलिहान हैं तो उसका स्वरूप बदला जा सकेगा। उसकी खरीद-फरोख्त की जा

अलका रॉय

सहायक प्रोफेसर,
जन्तु विज्ञान विभाग,
आर.एस.एम.महाविद्यालय,
धामपुर, बिजनौर

सकेगी। पिछले 25-30 वर्षों में शहरीकरण की रफ्तार ने मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। जंगल, खेल, मैदान और तालाब तक पाटकर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी हैं। हर शहर का नक्शा ही बदल गया है। यही कारण है कि आज लगभग हर बड़े-छोटे शहर, कस्बे यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी थोड़ी सी वर्षा के कारण जल भराव की समस्या विकट रूप लेती जा रही है। हाल ही में अपने देश की राजधानी दिल्ली की ही दुर्दशा से कौन परिचित नहीं है? कितनी बार दिल्ली जल भराव के कारण पूर्ण रूप से पैरालाइज्ड हो गयी तथा यातायात की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गयी। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मकाल से दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल संकट ने मानव जीवन को पूर्ण रूप से तोड़ दिया। कमोवेश पूरे भारतवर्ष में लगभग हर बड़े-छोटे शहरों में यही छवि है।

मूलरूप से देखा जाए तो इसका मुख्य कारण हमारे जल संरक्षण की ओर उठाए गये लचर कदम ही हैं। जिस प्रकार से हर छोटे-बड़े शहरों में तालाबों, जोहड़ों को पाटा जा रहा है। मात्र यह सोचे बिना कि इसके दूरगामी परिणामों में जल संकट और जल भराव दोनों हैं, उत्तर प्रदेश में इस कानून को खत्म करना एक पर्यावरण संरक्षण के नाम पर मजाक ही बन गया है। जल का संरक्षण या चक्रीकरण आने वाले दशकों के लिए अति आवश्यक है। तालाब, जोहड़ों या मैदानों की उपस्थिति इस इलाके की जैव विविधता का भी पूर्ण संरक्षण करती है जोकि उस इलाके में रहने वाले नागरिकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं।

जहां तक पानी की बात की जाए तो भारतवर्ष इस खजाने के लिए हमेशा अमीर ही रहा है। पानी की भाषा तक हमारे यहाँ समृद्ध है। पानी के इतने रूप, इतने पर्याय किसी और भाषा में दुर्लभ है। ऐसे में आज के समयकाल में जल संकट का गहराना वाकई चिन्ता का विषय है। बढ़ते जल संकट के साथ जल-संरक्षण और जल-प्रबंधन की चर्चा विश्व में चारों ओर जोर पकड़ती जा रही है।

पिछले कई वर्षों से यह बात अक्सर सामने आ जाती है कि 'अगला विश्वयुद्ध जल के लिए होगा'। मगर इस वर्तमान स्थिति में हम अपने ही देश में नजर दौड़ाये तो पायेंगे कि बांग्लादेश और भारत पानी को लेकर लड़ रहे हैं। पंजाब से निकलने वाली नदियां, जो पाकिस्तान में जाती हैं उनको लेकर भारत-पाकिस्तान में विवाद रहा है। देश के अन्दर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर जंग छिड़ी है जिसका उदाहरण अभी सितम्बर के प्रथम-द्वितीय सप्ताह में होने वाली विनाश-लीला से देश का हर व्यक्ति परिचित है। ऐसा देश जहां पुरखे मिट्टी के रंग, गंध से उस भूमि का स्वभाव जान लेते थे, सतह का दबाव तक पहचान जाते थे, उस भूमंडल भाग का जल के लिए त्राहिमाम होना शर्मनाक है। राजस्थान में जब इंदिरा नहर आई तो सरकारी तन्त्र को यह मालूम न था कि इस प्रदेश में पानी आएगा तो क्या परिस्थिति होगी? अधिकारियों ने वहां के स्थानीय लोगों के संचित ज्ञान की उपयोगिता को नहीं समझा और प्रथम चरण में जल के आते ही नहर के

आसपास लूणकरणसर में दलदल बन गया। बाद में इंजीनियरों को पता लगा कि नीचे जिप्सम की पट्टी है इसलिए पानी टकराकर रुक गया, वापस ऊपर आ गया। जिला जगह का नाम ही लूणकरणसर वहां के लोगों ने रखा हुआ था तो वहां वैज्ञानिक या इंजीनियरों ने क्यों नहीं उस विषय पर सोचा। और स्थानीय निवासियों के संचित ज्ञान का संज्ञान क्यों नहीं लिया? यहीं पर सरकार की जल नीति और समाज के जल दर्शन का फर्क सामने में आ जाता है। जल नीति सरकार पांच वर्ष के अपने कार्यकाल के लिए बनाती है और जल दर्शन वह है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। सैकड़ों, हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। उनके पीछे एक इकाई थी, बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यहीं इकाई, दहाई मिलकर सैकड़, हजार बनती थी। पर आज समाज के कुछ लोगों और सरकारी नीतियों ने उसे वापस शून्य में तब्दील करने की कसम खा ली है और किसी हद तक सफल भी हो गए हैं, इस जल संकट को ऊंचाईयों पर पहुंचाने के मुहाने पर। भारत जब आजाद हुआ तब केवल 382 गांव ऐसे थे जो जल से वंचित थे, आज इनकी संख्या 1 लाख 57 हजार है।

आधुनिक इंसान के बारे में एक बात खुशनुमा सत्य है कि वह मानवीयता और वैज्ञानिकता का पुतला है। पानी के विश्वव्यापी संकट की कहानी उसकी नादानी, बेईमानी और बेरहमी की कहानी है। विज्ञान बताता है कि जिस जल के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है उसकी मात्रा सीमित है। गणित बताता है कि पानी का सबसे अधिक उपयोग करने वाले प्राणी यानी इंसान की आबादी जितनी ही बढ़ती जाएगी, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उतनी ही कम होती जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा हो रहा है।

बीसवीं सदी के अंतिम पचास वर्षों में दुनिया की आबादी दुगुनी हुई और पानी की खपत छः गुनी। इसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध पानी इस अवधि में 58 प्रतिशत कम हो चुका है और ऐसा समझा जा रहा है कि 2050 तक वह 81 प्रतिशत कम हो चुका होगा। संसार का कुल 2.5-3 प्रतिशत पानी ही मीठा है। उसमें से भी दो तिहाई या तो कुल ध्रुव प्रदेशों और हिमनदों में जमा हुआ है या फिर जमीन में इतने गहरे दबा है कि वहां से निकालना कठिन है।

पानी के बारे में हमें अपनी सोच की समीक्षा करनी चाहिए। जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब हमारे गांवों में जल-प्रबंधन बेहतर था। धीरे-धीरे गांवों के जल स्रोत नष्ट हुए हैं समाज ने हजारों वर्षों के परिश्रम के बाद जिन परंपराओं का विकास किया, उसकी हमने उपेक्षा की है। वास्तव में जल-संकट के मामले में नवीन और प्राचीन की गुंजाइश नहीं होती है। प्रकृति पानी गिराने का तरीका अगर नहीं बदलती है तो पानी के बारे में हमें अपनी सोच की समीक्षा करनी चाहिए। पानी के बारे में प्रति घन लीटर और मीटर की जो पद्धति है वह योजनाकारों की शब्दावली है। इस पद्धति में उन्होंने देश को ज्यादा जल उपलब्ध करा दिया है, ऐसा नहीं है। पानी रोकने का तरीका कोई फैशन नहीं है जो हर साल दो साल में बदला जा सके। कुंड, तालाब, नदियों, पाइन आदि में

जल संग्रह होकर भू-जल को ऊपर उठाता है फिर साल भी हम नए पुराने अलग-अलग तरीकों से पानी खींच कर उपयोग में लाते हैं। पानी की इज्जत करना हमें सीखना होगा। वैज्ञानिकता का तकाजा है कि पानी के संरक्षण के कुंआ- बाबड़ी- पोखर जैसे तमाम पुराने उपाए फिर आजमाए जाए, ड्रिप सिंचाई करके कम पानी से ज्यादा पैदावार की जाए और घरों में पानी का किफायती इस्तेमाल किया जाए।

पुराने तालाब दुरूस्त करें। जल तालाब बनाना संभव न हो तो अपने घर, आंगन-खेत में जल संग्रहण हो तो अपने घर, आंगन-छत में जल संग्रहण करे ताकि 'बिन पानी सब सून' की भयावह कल्पना से बच सकें।

निष्कर्ष

जल स्रोत सिर्फ जलस्रोत नहीं है, अपितु धरती के गर्भ से निकलने वाले जल को अनेक रूपों में अनेक नामों से जाना जाता है। धारा, कुड, कुंआ, तालाब, पोखर, जोहड़, झरना सबकी अलग-अलग पहचान है। पानी बचाने के हमारे तरीके कैसे-कैसे थे, इसका अहसास इस बात से भी होता है कि घरों में बड़े बुजुर्ग यह कहते पाये जाते हैं कि जल की बर्बादी से लक्ष्मी बर्बाद होती है। समाज ने जल संरक्षण का अपना एक मैकेनिज्म विकसित कर लिया था जिसमें बरसात और बाढ़ का पानी भी संरक्षित किया जाता रहा है।

पानी सबकी मूलभूत आवश्यकता है। अंग्रेजकाल से ही पानी का सरकारीकरण हो गया था। समाज का

पानी के साथ रिश्ता टूटता सा गया। आज आमजन यह समझता है कि पानी का काम नदियों पोखरों का काम सरकार का है। वास्तविकता यही है कि सरकार बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन देखती है। बड़े बांध बड़ी सिंचाई योजनाएं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं आदि। इनमें कई महत्व की चीजें छूट जाती हैं जैसे वर्षा जल संग्रहण, छोटे तालाब, पोखर, भूजल इत्यादि और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पानी के प्रबन्धन और गर्वनेस से समाज का जुड़ाव। इसलिए यह प्रत्येक देश के नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी और आवश्यकता है कि कैसे वह पानी का मुद्दा अपना मुद्दा समझे और हर इकाई पर इसके संरक्षण के लिए सजग एवं संवेदनशील रहे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अश्वथ के. सुब्रह्मण्यम, द हिन्दू, दिनांक 15 दिसम्बर 2013, वॉटर, द लिटर सेक इज ए लिटर अर्नड, पृष्ठ-9
2. हिमांशु यादव, द हिन्दु इट्सनेशन विदइन नेशन, फरवरी 8, 2015,
3. नारायण लक्ष्मण कनसविग द लास्ट ड्रॉप - 3 मई 2016
4. अनुपम मिश्र, 'जल समृद्धि के देश में क्यों है ऐसी प्यास' मासिक कादम्बिनी, मई 2016
5. विजय जड़धारी, 'पानी एक बड़ी चुनौती', मासिक कादम्बिनी, मई 2016